गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

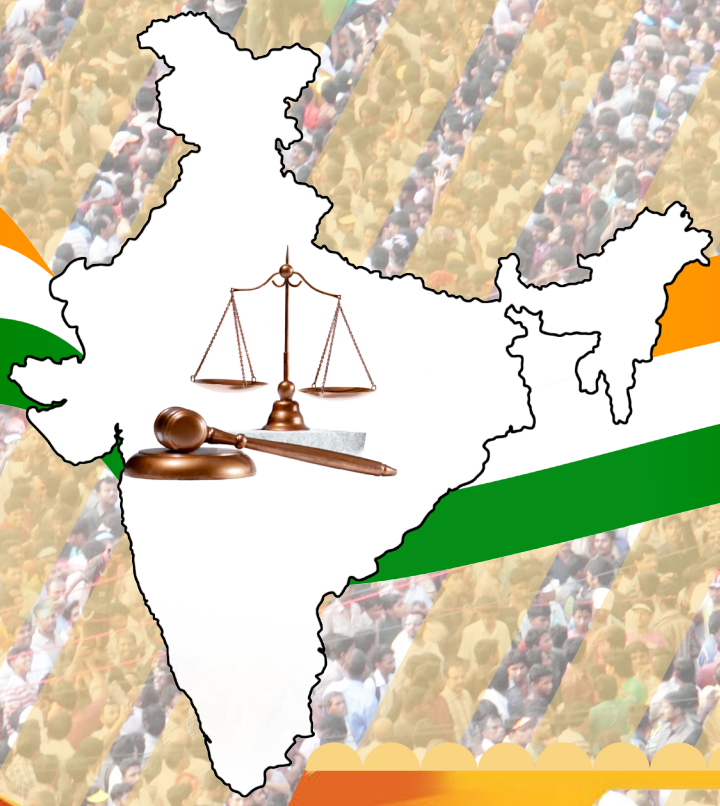

Technology

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

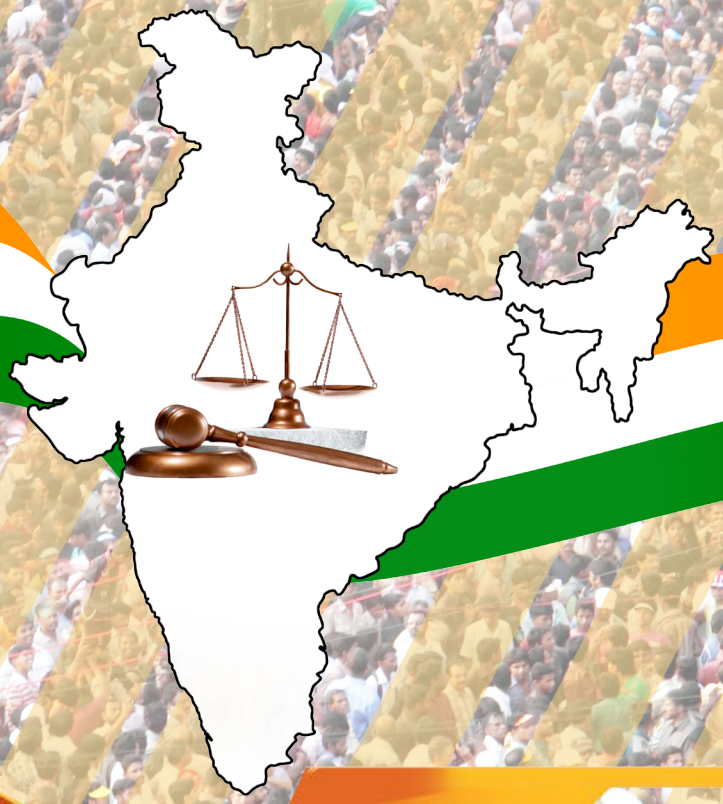

तकनीक

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

Digitising justice, elevating efficiency and credibility

♦Integrating technology across the legal spectrum

- The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023 introduces technology from the scene of the crime to investigation and trial, promising a swift and transparent justice system. The inclusion of technology is a significant step towards modernising the criminal justice system and harnessing the strength of modern scientific technology.

♦Elevating electronic evidence: A paradigm shift

- The new laws place electronic/digital evidence on equal footing with traditional documentary evidence for admissibility.

- Definition of 'documents' to include futuristic elements such as server logs, locational evidence, and digital voice messages.

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

न्याय का डिजिटलीकरण, सक्षमता और विश्वसनीयता बढ़ाना

कानूनी स्पेक्ट्रम में प्रौद्योगिकी का एकीकरण

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 ने एक तेज और पारदर्शी न्याय प्रणाली का वादा करते हुए अपराध स्थल से लेकर जांच और मुकदमे तक प्रौद्योगिकी की शुरूआत की। प्रौद्योगिकी का समावेश आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने और आधुनिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी की ताकत का उपयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्नत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यः एक आदर्श बदलाव

- नए कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल साक्ष्य को स्वीकार्यता के लिए पारंपरिक दस्तावेज साक्ष्य के समान माना गया है।
- दस्तावेजों की परिभाषा में सर्वर लॉग, स्थान संबंधी साक्ष्य और डिजिटल वॉयस संदेश भी शामिल।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को धारा 57 और 63 में बारीकियों को सहित रूप से बताया गया है।

- The admissibility of electronic records under Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA) 2023, particularly in Sections 57 and 63, have clearly enunciated the nuances of the same.

- BSA 2023 revolutionises the law of evidence, treating electronic evidence as equivalent to physical evidence in courts.

♦Streamlining secondary evidence: A futuristic approach

- The scope of secondary evidence broadens under BSA 2023, incorporating oral admissions, written admissions, and evidence of skilled person who has examined a document which contains numerous accounts or cannot be conveniently examined in Court.

- Two new forms introduced in the schedule expedite the authentication and appreciation of digital evidence, addressing challenges under previous statutes.

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 साक्ष्य के कानून में क्रांतिकारी बदलाव लाता है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को अदालतों में भौतिक साक्ष्य के बराबर मानता है।

द्वितीयक साक्ष्य को सुव्यवस्थित करना: एक भविष्यवादी दृष्टिकोण

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के तहत द्वितीयक साक्ष्य का दायरा व्यापक हो गया है, जिसमें मौखिक कबूली, लिखित कबूली और कुशल लोगों के साक्ष्य जिन्होंने उन दस्तावेजों की जांच की है जिसमें कई ऐसे कबूलनामे है जिन्हें आसानी से अदालत में जांच नहीं किया जा सकता।
- अनुसूची में पेश किए गए दो नए फॉर्म डिजिटल साक्ष्य के प्रमाणीकरण और मूल्यांकन में तेजी लाते हैं, पिछले कानूनों के तहत चुनौतियों का समाधान करते हैं।

साक्ष्य प्रस्तुति में क्रांति: एक पारदर्शी दृष्टिकोण

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 105 में जब्त की गई वस्तुओं की सूची और गवाहों के हस्ताक्षर सहित तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी की प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। मजिस्ट्रेट के समक्ष इन रिकार्डिंग को तुरंत प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान किया गया है ताकि साक्ष्य संग्रह में पारदर्शिता सुनिश्चित हो, और साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ न हो।

♦Revolutionising evidence presentation: A transparent approach

- Section 105 of BNSS 2023 introduces procedures for videography of search and seizure, including preparing lists of seized items and witness signatures. The records are presented immediately before magistrates to ensure transparency in evidence collection and discouraging fabrication of evidence.

♦Security measures for vulnerable victims: Protecting rights

- The new laws retain provisions for mandatory videography of police statements and audio-video recordings for vulnerable victims with physical or mental disabilities.

कमजोर पीड़ितों के लिए सुरक्षा उपायः अधिकारों की रक्षा

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 शारीरिक या मानसिक विकलांगता वाले कमजोर पीड़ितों के लिए पुलिस बयानों और ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग की अनिवार्य वीडियोग्राफी के प्रावधानों को बरकरार रखता है।